# आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की ओर

**जीरो टॉलरेंस के अंतर्गत की गई कार्रवाइयां उत्तर प्रदेश में 'बदली हुई व्यवस्था' का संदेश देने में सफल हुई हैं। अपराधमुक्त और अन्यायमुक्त वातावरण से उत्तर प्रदेश अपना परसेप्शन बदलने में सफल रहा है।**

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि 'हमारी सोच और हमारे सिद्धांत ये हैं कि गरीब और अशिक्षित लोग हमारे ईश्वर हैं, यही हमारा सामाजिक और मानवीय धर्म है।' इसी विचार को आत्मसात कर 24 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप सुरक्षित, समृद्ध, समुन्नत और आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए आज साढ़े चार वर्ष पूर्ण हो रहे हैं।

इस कालखंड में कोविड 19 जैसी वैश्विक महामारी ने देश और दुनिया को अपनी चपेट में लिया, उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा। लेकिन हमारे समक्ष जो चुनौतियां आयीं, उनसे न केवल सफलतापूर्वक निपटा गया बल्कि 'लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय और पथ अंत्योदय' के लक्ष्य को साधते हुए आपदा को अवसर में भी बदला गया। अंत्योदय से राष्ट्रोदय की संकल्पना को मूर्तरूप देते हुए हमारी वैचारिक दृष्टि ने अवध के मन, पूर्वांचल की आशा, बुंदेलखंड की अपेक्षा और पश्चिमांचल की अभिलाषा को संतुष्ट करने के क्रम में अनवरत श्रम किया है। जीरो टालरेंस के अंतर्गत की गयी कार्रवाइयां प्रदेश में 'बदली हुई व्यवस्था' का संदेश देने में सफल हुई हैं। यह संदेश ही हमारी पूंजी हैं। अपराधमुक्त, भयमुक्त और अन्यायमुक्त वातावरण के सृजन कर चतुर्दिक विकास का संदेश देकर उत्तर प्रदेश अपना परसेप्शन बदलने में सफल रहा है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ग्रोथ इंजन होता है। इसके बिना आर्थिक विकास तीव्र, धारणीय और प्रतिस्पर्धी नहीं हो सकता और न ही औद्योगिक क्षेत्र गति पकड़ सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्सप्रेस-वेज का एक संजाल विकसित करने के साथ-साथ वाटर वेज और एयर वेज को विकसित करने की दिशा में निर्णायक कार्य किया है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प 'आत्मनिर्भर भारत' का है। वह देश को 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं।

प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया था-रिफॉर्म, परफॉर्म तथा ट्रांसफॉर्म। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे अक्षरशः लागू किया है। बजट आवंटन बढ़ाने के साथ-साथ सरकार ने अब तक के कार्यकाल में प्रति व्यक्ति आय लगभग दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर उत्तर प्रदेश देश के अंदर 2015-16 की छठी अर्थव्यवस्था की तुलना में अब दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना चुका है। हाइवेज और एक्सप्रेस वेज अर्थव्यवस्था की 'जीवन रेखा' होते हैं। हाइवज, एक्सप्रेस वेज, लिंक एक्सप्रेस वेज और एयरवेज के साथ-साथ ईस्ट एवं वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के से सम्पन्न होकर उत्तर प्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ इन्फ्रास्ट्रक्चरल हब बनने जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में डॉयनॉमिक परिवर्तन लाएगा। यह परिवर्तन उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाने में निर्णायक साबित होगा।

उत्तर प्रदेश का भूगोल और प्रकृति उसे समृद्धि और विकास की बहुआयमी संभावनाओं से सम्पन्न बनाती है। इसके बावजूद भी 2017 से पहले तक इसकी गिनती बीमारू राज्य के रूप में होती रही क्योंकि इन संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने का विज़न विकसित नहीं हो पाया था। समन्वित नीतियों और साफ नीयत की कमी थी। 2017 में बीजेपी सरकार आने के बाद इस दिशा में कार्य आरम्भ हुआ। सरकार ने एक तरफ किसान, श्रमिक, युवा और महिला सहित सभी वर्गों की सुरक्षा, समृद्धि और कल्याण सुनिश्चित कराने की दिशा में बढ़ना आरम्भ किया वहीं दूसरी तरफ इन्फ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास की व्यूहरचना बनायी।

जनसांख्यिकीय वितरण की दृष्टि से देखें तो प्रदेश की सर्वाधिक आबादी अभी भी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। इसलिए किसान व कृषि को पहली कैबिनेट से वरीयता प्रदान की गयी जबकि इससे पहले कृषि और कृषक शासन की नीतियों के केंद्र में नहीं रहे थे। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने पहली बार अन्नदाता के हित व्यापक विमर्श का विषय बनाया। किसान को समय पर बीज और खाद मिले, इसकी चिंता की। उत्पादन लागतें कम हों, पैदावार में वृद्धि हो और उपज को बाजार व उपयुक्त कीमत मिले, इसकी व्यवस्था की गयी। आजाद भारत के इतिहास में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य तय करने का ऐतिहासिक कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही किया। हमारी सरकार ने तो किसान के ऋण की माफी से ही लोककल्याण की यात्रा प्रारंभ की थी।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2020-21 में प्रदेश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 618.49 लाख मीट्रिक टन रहा, जो अब तक का रिकार्ड उत्पादन है। इसके साथ ही सरकार द्वारा उनके उत्पादन की एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की गयी। विगत सरकारों में गन्ना किसानों के नाम पर राजनीति की गयी लेकिन किसानों को किसी ने नहीं पूछा। हमारी सरकार ने गन्ना किसानों का अब तक करीब 1.45 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज किसान उन्नत तकनीक से जुड़कर कृषि के विविधीकरण, अतिरेक उत्पाद और वृद्धिशील आय के साथ प्रदेश को समुन्नत बनाने की दिशा में अग्रसर हो रहा है।

कानून-व्यवस्था के बारे में हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति से आम जन सुरक्षित महसूस कर रहा है और कारोबारी निश्चितता के साथ के साथ अपना व्यवसाय कर रहा है। इसका परिणाम भी 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' इंडेक्स पर प्रदेश की रैंक में आए उछाल (14 से 2) में देखा जा सकता है। यह बताता है कि निवेशकों और उद्यमियों की दृष्टि में उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बनने में कामयाब रहा है। बीते 54 महीनों में प्रदेश के 01 करोड़ 61 लाख से अधिक नौजवानों को निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हुआ, 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया गया और लगभग 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गयी। युवाओं के हौसलों को पंख देने के लिए उन्हें साधन-संपन्न बनाने पर हमारा जोर है। इस दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में युवा प्रतिभाओं का 'अभ्युदय' हो रहा है।

मातृशक्ति की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन किसी समाज का दर्पण होता है। नारी का सम्मान हमारी सनातन परम्परा रही है। स्मृतियों में भी कहा गया है- 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः।।' अर्थात जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं और जहां स्त्रियों की पूजा नहीं होती, उनका सम्मान नहीं होता, वहां किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। अतः आरंभ से ही हमारी सरकार ने मातृशक्ति की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलम्बन की दिशा निर्णायक कार्य किए। एंटी रोमियो स्क्वायड के गठन से लेकर मिशन शक्ति तक के किए गये कार्यों के क्रम में इसे देखा जा सकता है। समवेत प्रयासों से प्रदेश में 10 लाख स्वयं सहायता समूहों से 01 करोड़ से अधिक महिलाओं को सम्बद्ध कर उनके आर्थिक उन्नयन का मार्ग प्रशस्त हुआ तो बैंकिग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी योजना के माध्यम से 58,758 महिलाओं को बैंकिग व्यवस्था से जोड़ने और हर गांव तक बैंक को पहुंचाने का नवाचारी प्रयोग भी फलीभूत हुआ है।

उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त कर सके इसके लिए अर्थव्यवस्था का प्रतिस्पर्धी, तीव्र विकास आधारित और समावेशी बनना आवश्यक था। बीते साढ़े चार वर्षों में उत्तर प्रदेश 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की राष्ट्रीय रैंकिंग में दूसरे पायदान पर पहुंचा है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के मामले में गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, देश सर्वश्रेष्ठ व्यवसायिक व निवेश गंतव्य बना है। जनसांख्यिकीय लाभांश की दृष्टि से ये संकेतक सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक गांव और जनपद स्वालंबी बने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समृद्ध हो तथा प्रदेश बेरोजगारी और पलायन के दंश से स्थाई रूप से हो इस उद्देश्य 'एक जनपद-एक उत्पाद' कार्यक्रम को नवोन्मेष के साथ आगे बढ़ाया गया। अर्थव्यवस्था का 'पॉवर इंजन' कही जाने वाली लाखों एमएसएमई इकाइयों को वित्तीय सुविधा प्रदान कर गति प्रदान की गयी। इससे आर्थिक विकास तेज हुआ और रोजगार सृजन में संचयी वृद्धि देखने को मिली। यह 'नए भारत के नए एवं आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' की नई तस्वीर की झलक है। प्रदेश वही है, लोग वही हैं, मेधा वही है। केवल दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति बदली है। अति साधारण व्यक्ति भी अब स्वयं को शासन का हिस्सा समझता है। विगत 54 महीनों में यही परिवर्तन, यही विश्वास हमने हासिल किया है।

**618**
लाख मीट्रिक टन से ज्यादा रहा खाद्यान्न उत्पादन 2020-21 में

**1.45**
लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गन्ना किसानों का

**01**
करोड़ 61 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ निजी क्षेत्र में 54 महीनों में